भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4289

दिनांक 18.03.2026 को उत्तर देने के लिए

सतत विकास लक्ष्य की दिशा में कार्य नीतियाँ

4289. **श्री कल्याण बनर्जी:**

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2025-30 के दृष्टिकोण के लिए सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में कार्य नीतियाँ अपनाई हैं, जिनमें राज्य परिवर्तन संस्थानों (एसआईटी) का सृजन करना और राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को सशक्त बनाना शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वास्थ्य, अवसंरचना और ग्रामीण विकास के लिए राज्य-वार लक्षित क्षेत्र और योजनाएँ क्या हैं; और

(ग) न्यू इंडिया @75 के लिए कार्य नीतिक योजना का ब्यौरा क्या है, जिसमें 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का विस्तृत विवेचन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख) सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कई प्रमुख पहलें शुरू की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), पीएम आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत), सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान 2.0, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-ऊषा), मुद्रा योजना, सौभाग्य योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन (जेजेएम), स्वच्छ भारत मिशन, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन, पर्यावरण के लिए जीवनशैली (लाइफ) मिशन, आकांक्षी

जिला और ब्लॉक कार्यक्रम, स्टार्ट-अप इंडिया, अटल शहरी कायाकल्प और परिवर्तन मिशन (अमृत) शामिल हैं। राज्य सहायता मिशन के तहत, दीर्घकालिक विज़न, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और परिणाम-केंद्रित शासन के लिए राज्य परिवर्तन संस्थाओं का गठन किया गया है। नीति आयोग ने राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों को मजबूत करने के लिए एक रोडमैप विकसित किया है जो संरचनात्मक सुधारों, क्षमता निर्माण और राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों के बीच बेहतर सहयोग की दिशा में उठाए गए कदम संबंधी परामर्श देता है और राज्यों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) ईकोसिस्टम को गति देने में सहायता कर सकता है। भारत सरकार राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को उप-राष्ट्रीय स्तर की निगरानी तंत्र विकसित करने में सहायता प्रदान करती है, जो उन्हें एसडीजी की निगरानी करने में सहायता करता है।

(ग) सरकार ने 'न्यू इंडिया @75 के लिए कार्यनीति' नामक एक राष्ट्रीय विकास कार्यनीतिक दस्तावेज तैयार किया है, जो देश भर में कृषि, उद्योग, अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, शासन और पर्यावरण जैसे सेक्टरों को कवर करने वाले इकतालीस प्रमुख क्षेत्रों में नीतिगत प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करता है। यह दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है जिसे निम्नलिखित https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-01/Strategy_for_New_India_2.pdf. पर देखा जा सकता है।

*****